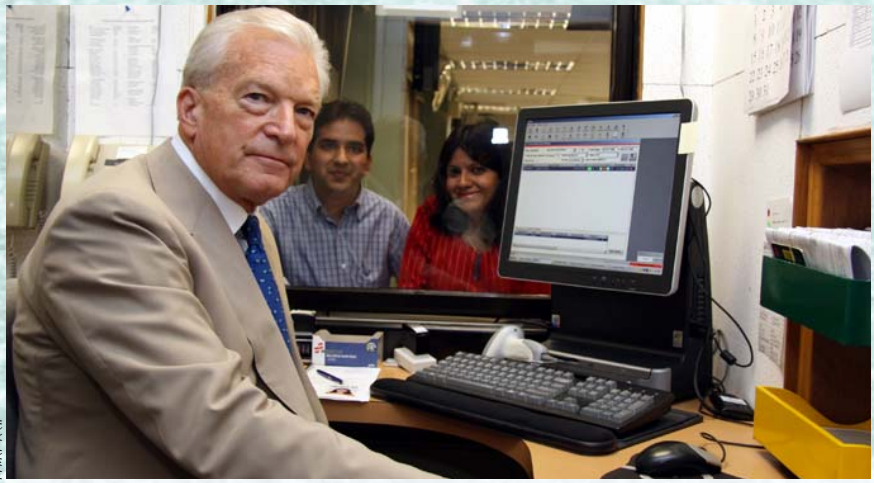

विकास नरूला

भारतीय और अमेरिकी ''कारोबार एवं लोगों के स्तर पर आपस में इतने ज्यादा संपर्क कायम कर रहे हैं कि यह कभी भी किसी के भी आकलन से ज्यादा है। दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई है और अमेरिकी दूतावास इस प्रक्रिया को आसान बनाने को प्राथमिकता दे रहा है।'' 5 अक्टूबर को नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में वीजा प्रोसेसिंग में अन्य अमेरिकी राजनयिकों के साथ शामिल राजदूत डेविड सी. मल्फर्ड ने ये विचार व्यक्त किए। ''हमारे देशों के बीच नए व्यापार में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई है। हमने कारोबार के लिए जाने वाले लोगों की यात्रा को आसान बनाने के लिए कदम उठाए हैं।'' वीजा के इच्छुक लोगों को बुलाने की प्रतीक्षा अवधि भारत में अब सभी अमेरिकी कांसुलेट पर घटकर हाल के महीनों में एक हफ्ते रह गई है और फीस भी कम हुई है ।

भारतीय और अमेरिकी कंपनियां साथ काम करने की इच्छुक

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मामलों के अंडर सेक्रेटेरी फ्रैंकलिन एल. लैविन के साथ भेंटवार्ता

मई में नई दिल्ली की अपनी पिछली यात्रा के बाद से अंतरराष्ट्रीय व्यापार मामलों के अंडर सेक्रेटेरी फ्रैंकलिन एल. लैविन और उनकी टीम भारत के लिए बहु-नगरीय, बहु-क्षेत्र व्यापार विकास प्रतिनिधिमंडल की योजना पर काम कर रहे थे - कहीं भी जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल। प्रतिनिधिमंडल के भारत आगमन के ठीक पहले अंडर सेक्रेटेरी ने दोनों देशों के लाभ के लिए आपसी व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में स्पैन से बातचीत की।

स्पैन: अमेरिकी व्यापार जगत के 200 अग्रणी लोगों की यात्रा और उनकी भारतीय कारोबारी जगत के मुखियाओं से बातचीत से निसंदेह बहुत से आइडिया प्रकट होने के अलावा दिलचस्पी भी जागृत होगी और प्रस्ताव भी आएंगे। लेकिन भारत में व्यापार का अमेरिकियों का उत्साह नियमन बाधाओं, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण में ढिलाई, कानून पर असमान अमल और भ्रष्टाचार से बाधित रहा है। ये चीजें किस तरह बदलेंगी?

अंडर सेक्रेटेरी लैविन: यह प्रतिनिधिमंडल इस बात को प्रदर्शित करता है कि अमेरिकी कंपनियों का भारतीय बाजार में दिलचस्पी का स्तर ऊंचा है और यह दिलचस्पी बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि भारतीय कंपनियां अमेरिका की कंपनियों के साथ काम करने को उत्सुक हैं। लेकिन दोनों देशों की कंपनियां जिन वाणिज्यिक नीतियों के तहत काम करती हैं, उनमें बदलाव भारत की केंद्र और राज्यों की लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी गई सरकारों को ही लाना होगा। अपनी यात्रा के दौरान में अपनी वाणिज्यिक वार्ता के तहत अपने भारतीय समकक्ष से मिलूंगा और भारत में व्यापार के रास्ते में आने वाली बाधाओं पर हमारी चिंताओं और इन बाधाओं को दूर कर किस तरह अमेरिका भारत व्यापार फल-फूल सकता है, इस पर

चर्चा करेंगे।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भारत में व्यापार करने के सिलसिले में क्या चिंताएं जताई हैं, वे क्या सवाल पूछ रहे हैं?

स्मार्ट कारोबारी लोगों की तरह प्रतिनिधिमंडल के सदस्य संभावित ग्राहकों पर ध्यान दे रहे हैं और उनके द्वारा सबसे ज्यादा चिंता यही जताई जा रही है कि भारत में उनके उत्पादों की मांग कैसी है। कुछ बड़ी कंपनियों को इस बात की अच्छी समझ है और वे खरीददारों की तलाश कर रही हैं। लेकिन अन्य जानना चाहते हैं कि भारतीय बाजार में अपने उत्पाद लाने की श्रेष्ठ रणनीति क्या है? उनके सवालों में शामिल है - क्या हमें संयुक्त उपक्रम स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए? हम वितरक भागीदार कैसे चुनें? सबसे बेहतर भागीदार रणनीति क्या है? अच्छी मार्केटिंग भागीदारी को जारी कैसे रखें?

अमेरिका के अग्रणी कारोबारी लोगों को भारत में कारोबार करने के सकारात्मक घटनाक्रम के बारे में खास तौर पर क्या बताया जा सकता है?

भारत ने ज्यादातर औद्योगिक उत्पादों पर लगातार शुल्क में कटौती कर सीमा शुल्क को इस स्तर पर पहुंचा दिया है कि ज्यादातर तैयार उत्पादों पर शुल्क 12.5 फीसदी ही लगता है। यह कथित उच्च शुल्क भी 10 फीसदी तक लाए जाने की बात है। इसी तरह भारत ने अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को उदार बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इससे सकारात्मक बातों को प्रोत्साहन मिला है और अमेरिकी कंपनियों से वाणिज्यिक प्रवाह बढ़ा है। भारत को अमेरिकी निर्यात वर्ष 2002 से वर्ष 2005 के बीच दो गुना हो गया और इस साल अगस्त में यह 20 फीसदी और बढ़ गया। वर्ष 2002 से 2005 के बीच भारत में अमेरिकी प्रत्यक्ष निवेश दो गुना हो गया। भारत में व्यापार और निवेश नीतियों के और उदारीकरण से अमेरिकी कंपनियों की भारत में दिलचस्पी और बढ़ेगी।

भारत में राय बनाने में आगे रहने वाले एक प्रभावी वर्ग को आशंका है कि अधिक और पहले से ज्यादा मुक्त व्यापार का मतलब है कि भारत में विदेशी उत्पाद छा जाएंगे और स्थानीय कंपनियां प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगी, विदेशी कंपनियों के लिए श्रम संरक्षण कानून में संशोधन करने का दबाव बढ़ेगा और अमेरिकी कारोबारी ज्यादा पैसा बना सकें, इसके लिए भारत की कारोबारी संस्कृति में बदलाव आएगा। अमेरिका के इस बड़े व्यापारिक प्रयास से भारत की छोटी और मझोली कंपनियों को क्या फायदा होगा?

वर्ष 2002 और 2005 के बीच भारत का वैश्विक निर्यात दो गुना हो गया है जो स्पष्ट करता है कि भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। इससे यह भी पता चलता है कि आर्थिक उदारीकरण ने भारत की अंतरराष्ट्रीय व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद की है। प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का मौका देने पर भारतीय कंपनियां श्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यापार और प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी से भारतीय कंपनियों और उपभोक्ताओं, दोनों को ही लाभ मिलेगा। बौद्धिक संपदा अधिकारों के बेहतर संरक्षण और अमल, विदेशी निवेश पर अंकुश हटाने सहित आर्थिक उदारीकरण के लिए और आगे के कदम सभी आकार की भारतीय कंपनियों को व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराएंगे। **- लॉरिंडा कीज लौंग**